

भुगतान शेष से आपका क्या आशय है? भुगतान शेष के असंतुलन में सुधार के उपायों की विवेचना करें।

Or, भारत में व्यापार असंतुलन के कारणों की विवेचना कीजिये तथा सरकार द्वारा इस असंतुलन को रोकने के प्रयासों का वर्णन कीजिये।

Ans. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है और कुछ वस्तुओं का आयात करता है। आयात की गई वस्तुओं का उसे भुगतान करना होता है और निर्यात की गयी वस्तुओं का भुगतान लेना होता है। अतः विदेशी व्यापार से संबंधित वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिये प्रत्येक देश को अपने आयातों और निर्यातों की कुल मात्रा तथा मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है। इस संबंध में व्यापार संतुलन (Balance of Trade) तथा भुगतान संतुलन (Balance of Payments) दो काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनके विश्लेषण द्वारा ही किसी देश के विदेशी व्यापार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्भावनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है।

व्यापार शेष या संतुलन का अर्थ (Meaning of Balance of Trade) : व्यापार शेष का संबंध किसी देश द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ दृश्य मर्दों के आयात और निर्यात के लेखा-जोखा से है। यह छोटे, अतिरेक (surplus) अथवा साम्य किसी भी स्थिति में हो सकता है। साधारण शब्दों में किसी देश का व्यापार-संतुलन उस देश के आयातों और निर्यातों के संबंध को बताता है। यह एक ऐसा विवरण होता है जिसमें वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का विस्तृत ब्यौरा दिया होता है। व्यापार-संतुलन में केवल दृश्य (Visible) निर्यातों तथा आयातों को सम्मिलित जाता है

और अदृश्य निर्यातों तथा आयातों का उसमें कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

भुगतान-शेष या संतुलन का अर्थ (Meaning of Balance of Payments) :

साधारण शब्दों में एक निश्चित अवधि में एक देश को विदेशों से जो भुगतान मिलता है, और जो भुगतान करना होता है इसके क्रमबद्ध विवरण को भुगतान संतुलन कहा जाता है। बैन्हम के अनुसार, "एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित काल के भीतर उसके बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है।"

किसी देश का भुगतान संतुलन उसके सम्पूर्ण विदेशी लेन-देन (Credits and Debits)

का एक विवरण अथवा चिट्ठा होता है। इसके बायीं ओर सभी लेनदारियाँ तथा दायीं ओर सभी देनदारियाँ दिखायी जाती हैं। लीग ऑफ नेशन्स ने भुगतान संतुलन के विवरण में सम्मिलित विभिन्न मदों का वर्गीकरण दो शीर्षकों के अंतर्गत किया- (अ) चालू खाता एवं (ब) पूँजी खाता।

(अ) चालू खाता (Current Account) : चालू खाते में व्यापार की दृश्य (Visible) तथा अदृश्य (Invisible) मदें सम्मिलित होती हैं। अमौद्रिक उद्देश्यों से विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण का आयात-निर्यात तथा अनुमान में भूल-चूक की सम्भावनायें भी इसी खाते में सम्मिलित रहती हैं।

(ब) पूँजी खाता (Capital Account) : पूँजी खाते में पूँजीगत भुगतान और प्राप्तियों का लेखा जोखा होता है। इसमें ऋणों की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ, करेंसी, स्वर्ण हस्तान्तीकृत किया जा सकता है

(अ) दृश्य मदें (Visible Items) : इस श्रेणी में वे समस्त लेन-देन शामिल किये जाते हैं जिनमें एक देश से जाने वाली या उसमें प्रवेश करने वाली वस्तुयें (भौतिक वस्तुयें) देखी जाती हैं। इन्हें बन्दरगाहों पर लेखांकित कर लिया जाता है।

(ब) अदृश्य मदें (Invisible Items) : उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त अन्य सभी लेन-देनों को अदृश्य मदें कहा जाता है। इसके अंतर्गत सेवायें (बैंकिंग, बीमा, विशेषज्ञ, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा) लाभांश, विदेशी सरकारों द्वारा व्यय तथा उपहार आदि की लेनदारियों (receipts) और देनदारियों (Payments) को जोड़कर चालू खाता का लेखा प्राप्त होता है। "द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत का व्यापार संतुलन मुख्यतः इसके अनुकूल रहता था।

युद्ध के पश्चात विभिन्न कारणों से भारतीय व्यापार संतुलन नियमित रूप से देश के प्रतिकूल होने लगा।

व्यापार असंतुलन के कारण (Causes of Adverse Balance of Trade)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के व्यापार संतुलन के निरन्तर प्रतिकूल रहने के निम्नांकित कारण हैं

1. देश-विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Effect of Partition of the Country) : देश-विभाजन का हमारे व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विभाजन के पूर्व भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में जूट एवं कपास का महत्वपूर्ण स्थान था। किन्तु,

विभाजन के फलस्वरूप हम इनका बहुत बड़ी मात्रा में आयात करने लगे क्योंकि जूट एवं कपास उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। 1952 ई. में भारत को 115 करोड़ रुपये मूल्य की कृपास तथा 23.5 करोड़ रुपये मूल्य के कच्चे जूट का आयात करना पड़ा था।

2.

अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात (Excessive Import of Foodgrains) : व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण खाद्यान्नों का अत्यधिक मात्रा में आयात था। वर्मा के भारत से अलग होने तथा 1947 ई. में देश-विभाजन ने खाद्यान्न के अभाव को बहुत बढ़ा दिया। इसी बीच देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्रायः 1 करोड़ से भी अधिक के हिसाब से वृद्धि होने लगी। इन सभी कारणों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा।

3. किन्तु आजकल खाद्यान्न का आयात प्रायः समाप्त हो गया है तथा अब तो देश से गेहूँ एवं चावल का निर्यात भी किया जाने लगा है। 1991-92 ई. में 756 करोड़ रुपये के चावल का निर्यात किया गया था।

4. यन्त्र एवं अन्य उपकरणों के आयात में वृद्धि (Increase in the Import of Plant and Machineries): व्यापार संतुलन के प्रतिकूल होने का तीसरा प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध के

बाद यन्त्रों के आयात में अत्यधिक वृद्धि होना है। युद्धकाल में मशीनों का आयात प्रायः बन्द रहा, अतः युद्ध समाप्ति के बाद पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन तथा नये कारखानों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में मशीनों का आयात किया जाने लगा। आजकल तो पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में मशीनों का और भी अधिक मात्रा में आयात करना पड़ रहा है। इस प्रकार जहाँ 1938 ई. में केवल 20 करोड़ रुपये की मशीनों का आयात हुआ था, वहाँ 1999-2000 ई. में 19,850 करोड़ रुपये की मशीनों का आयात किया गया था।

5.

पेट्रोल तथा रासायनिक खाद के आयात में अत्यधिक वृद्धि (Increase in the Import of Petroleum and Chemical Fertilizers) : पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण इसके आयात पर बहुत अधिक रकम व्यय करनी पड़ रही है। 1970-71 में केवल 135 करोड़ रुपये मूल्य के पेट्रोलियम का आयात किया गया था। 1991-92 में 13,127 करोड़ रुपये मूल्य का पेट्रोलियम आयात किया गया था जो देश के कुल आयात का लगभग 30 प्रतिशत था। इसी प्रकार 1991-92 ई. में 2,352 करोड़ रुपये की रासायनिक खाद का आयात किया गया था।

6.

सरकार द्वारा व्यापार असंतुलन रोकने के प्रयास भारत सरकार द्वारा व्यापार असंतुलन को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये गये हैं

7.

आयात पर कठोर नियंत्रण (Rigid Import Control) : सर्वप्रथम तो सरकार द्वारा आयात पर तरह-तरह के कठोर नियंत्रण लगाये गये कई तरह के आयात पर रोक लगा दी गयी तथा किसी भी वस्तु के आयात के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना अनिवार्य बना दिया गया। आयात-नियंत्रण की इस नीति के अन्तर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात की ही अनुमति दी जाती है। किन्तु, 1991-92 ई. की उदार आर्थिक नीति के अन्तर्गत आयात नीति को भी उदार बना दिया गया है।

8.

भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Indian Rupee) : निर्यात की मात्रा को बढ़ाने तथा आयात को कम करने के लिए सितम्बर, 1949 ई. में भारत सरकार द्वारा रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे हमारे को विशेषतः डॉलर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला तथा व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता भी कुछ कम हुई। किन्तु, इस • अवमूल्यन का प्रभाव बिल्कुल अस्थायी रहा। अतः पुनः 6 जून, 1966 ई. को सरकार ने अपनी रुपये का अवमूल्यन किया। किन्तु, इसका भी इच्छित परिणाम नहीं हो सका। पुनः 1991 ई. में सरकार ने जून के प्रारम्भ में अपनी मुद्रा का दो बार अवमूल्यन किया था।

9.

निर्यात को प्रोत्साहन (Export Promotion) : निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने कुछ प्रमुख वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क को कम कर दिया है। साथ ही, निर्यात बढ़ाने के

लिए निर्यात-विकास परिषदों (Export Promotion Councils) का संगठन किया गया। इधर निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों में सरकार को पर्याप्त सफलता भी मिली। किन्तु फिर भी निर्यात अभी आयात की तुलना में कम ही बढ़ रहा है।

10.

खाद्यान्न, जूट तथा कपास की खेती को प्रोत्साहन प्रदान करना: देश में खाद्यान्न, जूट तथा कपास की खेती को प्रोत्साहित किया जाने लगा है जिससे इनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद देश में हरित क्रांति (Green Revolution) का सूत्रपात हुआ जिससे खाद्यान्नों के आयात में बहुत कमी आ गयी। आजकल तो खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भारत खाद्यान्नों का पुनः निर्यातक देश होते जा रहा है।

11.

पेट्रोल की खोज एवं बचत : पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में देश में सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाने के साथ-साथ इनके आन्तरिक उपभोग को कम करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

12.

आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) : विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता को रोकने के लिए आयात प्रतिस्थापन यानी आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन बढ़ाने, या इनकी जगह अन्य वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सातवीं योजना में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था।

इस प्रकार व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। किन्तु, इन प्रयत्नों में अभी कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो पायी है। 1966-67 ई. में भारत का व्यापार संतुलन 892 करोड़ रुपये से प्रतिकूल था। इसके बाद के वर्षों में निर्यात में कुछ वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप 1969-70 ई. में व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता घटकर 176 करोड़ रुपये हो गयी। 1976-77 ई. में तो निर्यात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई जिससे व्यापारिक प्रतिकूलता बिल्कुल ही समाप्त हो गयी। किन्तु इसके बाद पेट्रोलियम के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण व्यापारिक प्रतिकूलता में भी पुनः बहुत वृद्धि हुई। 1980-81 ई. में व्यापार संतुलन 5,838 करोड़ रुपये, 1988-90 ई. में 7,900 करोड़ रुपये तथा 1990-91 ई. में 10,533 करोड़ रुपये से बढ़कर 44,042 करोड़ रुपये हो गया जिसके फलस्वरूप व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता 1990-91 ई. की तुलना में घटकर 3,809 करोड़ रुपये हो गयी।